कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–899/1385 रायपुर, दिनांक 06/06/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of 169.0231 ha. (77.3042 ha in Korba Forest Division 90.9718 ha. in Dharamjaigarh Forest Division and 0.7471 ha. in Jashpur Forest Division) of forest land under Forest Conservation Act. 1980 in favour of Project Director National Highway Authority of India. for development of Urga-Pathalgaon Section of NH-130 A (Raipur-Dhanbad Econoic Corridor). from Km 70.200 to 157.745 km in Korba Dharamjaigarh & Jashpur Districts in the State of Chhattisgarh-reg.**

संदर्भ:–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-8/21/ 2023/ IRO-Raipur / 1563 दिनांक 08.02.2024
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक/1275 दिनांक 18.04.2024

–0–

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र – 1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 अंतर्गत उरगा–पत्थलगांव (रायपुर–धनबाद इकोनॉमी कॉरीडोर) राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए रकबा 169.0231 हे. (धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 90.9718 हे. कोरबा वन मंडल अंतर्गत 77.3042 एवं जशपुर वन मंडल अंतर्गत 0.7471) वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु (VSESA-1980) के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से प्रेषित किया है, बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:–

S.No.	Condition	Compliance
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
(ii)	a. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 171.4929 ha area spread in9 patches of Non-forest land in Balodabazar Forest Division. The Compensatory afforestation area has been identified In Balodabazar Forest Division, Dist-Balodabazar-Bhatapara, The Compensatory afforestation will becarried out at the cost of the user agency. As far as possible, mixture of local indigenous species shall be planted	वनमण्डल बलौदाबाजार अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपेण हेतु प्रस्तावित ख.नं. 377, 24/1, 87/1क, 1643/4, 1/1, 1040/1/क/1, 8/1,85/1, 404/1क, 452, 586/1, 243/1 में कुल रकबा 171.4929 हे. उपयुक्त स्थल चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की वर्ष 2023–24 की दर राशि रूपये 9,66,666/– की दर से कुल राशि 16,57,76,356.00 (शब्दो में– सोलह करोड़ संतावन लाख छेहत्तर हजार तीन सौ छप्पन रू. मात्र) कैम्पा खाता में ई–पोर्टल के माध्यम से RTGS/IBKLR92024031300008706 दिनांक 13.03.2024 को जमा किया गया है। वर्ष 2024–25 की प्रचलित दर से वैकल्पिक वृक्षारोपण की अंतर की राशि

	and monoculture of any species may be avoided;	रूपये 3,48,15,459.272 दिनांक 03.06.2024 से कैम्पा खाता में जमा किया गया है। वेब चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
	b. The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Departmentor the revenue forest land, as the case may be, shall be notified by the State Governmentas Protected Forests under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under there levant section(s) of" the local Forest Act, before issue of the 'Final' approval underthe Adhiniyam. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with acopy of the original notification declaring the non-forest land as PF, along with compliance of 'in-principle' approval;	प्रकरण के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना तैयार कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया था जिसके लिए कलेक्टर, बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) के आदेश पत्र दिनांक 21.08.2023; दिनांक 27.05.2024 एवं दिनांक 27.05.2024 द्वारा 169.6752 हे. प्रस्तावित राजस्व भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण आदेश जारी कर वन विभाग के नाम से नामांतरण किया जा चुका है। अधिसूचना प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में पृथक से तैयार कर प्रेषित किया जावेगा **(संलग्नक–2बी)**
(iii)	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained hi" 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्था द्वारा प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं परिवर्तित किये जाने के उपरांत क्षेत्र को आर.सी.सी. पीलर्स, सर्वे हेतु वन विभाग के मांग पत्र अनुसार देय राशि आवेदक संस्था द्वारा जमा किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
(iv)	a. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 169.0231 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 3011 0/2002, 01108/2003, 28103/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 20211995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No.5-111998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No.5-2/2006-FC dated 03110/2006, letter No. 5-3/2007-FC dated 05102/2009 and letter No. 5-3/2011- FC(Vol-I) dated 06.01.2022 in this regard;	NPV हेतु राशि रू. 22,09,21,815.00 (रू. बाईस करोड़ नौ लाख ईक्कीस हजार आठ सौ पन्द्रह मात्र) मांग अनुसार इस विभाग द्वारा RTGS/IBKLR920240 31300008706 दिनांक 13.03.2024 को CAMPA मद में भुगतान किया जा चुका है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
	b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है तो आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**

(v)	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency witb the State Forest Department;	आवेदक संस्थान, वन विभाग के परामर्श अनुसार वृक्षों की कटाई को कम किया जावेगा और बाहरी पंक्ती में वृक्षों की संख्या को अधिकतम बनाये रखेगी। वृक्षों के कटाई हेतु आवेदक संस्थान द्वारा राशि 3,01,86,558/– रूपये पी.डी खाते के माध्यम से वन मंडल कार्यालय में जमा किया गया है **(संलग्नक–5)**
(vi)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferredl deposited to CAMPA fund only through e-portai *(https.Z/parivesh.nic.in/);*	सभी प्रकार का भुगतान CAMPA मद में e-portal के माध्यम से जमा किया गया है एवं एवं अंतर की राशि जमा करने हेतु आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–6)**
(vii)	The State Government of Chhattisgarhl Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No.2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- II sub-rule (7) of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 dated 29.11.2023;	कलेक्टर जशपुर का पत्र दिनांक 28.03.2024; रायगढ़ का पत्र दिनांक 09.04.2024 एवं कोरबा का पत्र दिनांक 26.03.2024 को जारी वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित FRA अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–7)**
(viii)	The proposed project is passing through Lemru Elephant Reserve, and hence necessary approval of National Board for Wildlife is to be obtained for the purpose. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with the compliance of 'in-principle' approval;	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर द्वारा दिनांक 14.05.2024 से उक्त शर्त विलोपित किया गया है **(संलग्नक–8)**
(ix)	Suitable site-specific wildlife mitigation plan (including required number underpasses etc at suitable places) shall be prepared and duly approved by the CWLW. Such mitigation plan and all other recommendation of the SC-NBWL shall be implemented at the project cost. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with the compliance of 'in- principle' approval;	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा दिनांक 02.05.2024 से अनुमोदित किया गया है तथा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना की राशि रूपये 15,73,26,400/– रूपये कैम्पा मद में जमा की गई है। वन विभाग द्वारा चिन्हित तथा CWLW/NBW के द्वारा approved स्थानों पर वन्य हाथी हेतु अंडरपास/ओवरपास एवं अन्य हेतु निर्धारित गाईडलाईन अनुरूप बानाया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)**
(x)	Site-specific Soil Conservation Plan shall be prepared and implemented at the project cost and copy of the such plan shall be submitted to the sub office Raipur. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with the compliance of 'in-principle' approval;	Soil Conservation Plan की राशि 6000000.00 (शब्दो में साठ लाख रू. मात्र) RTGS / IBKLR920240 31300008706 दिनांक 13.03.2024 को CAMPA मद में भुगतान किया जा चुका है एवं Soil Conservation Plan संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
(xi)	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure all structures proposed by the user agency such as 21 minor bridges,6 Major bridges, 27 Major	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)**

	bridges cum viaduct, 1 Elephant Overpasses, 11 Elephant Underpasses, 2 Overpasses, 1 Flyover, 18 Light Vehicle Underpasses, 6 Vehicle Underpasses, 1 ROBs, 159 Box Culverts, 69 Box Culverts etc;	
(xii)	The trees having bird nests both in forest as well as non-forest land shall not be felled without written permission from the DFOs concerned;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)**
(xiii)	The user agency shall arrange to raise strip plantation on either side of the road and central verge at project cost, as per IRC specification, with maintenance of 7-10 years. The user agency shall also submit design of providing at least 2-3 rows of long rotation indigenous trees, as per provision of IRC-SP-21-2009 (Guidelines on landscaping & tree plantation), on either side ofthe road before final clearance;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)**
(xiv)	Overburden shall not be-dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–13)**
(xv)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–14)**
(xvi)	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–15)**
(xvii)	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–16)**
(xviii)	The designing of culvertslbridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done insuch a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–17)**
(xix)	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–18)**
(xx)	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–19)**

(xxi)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	Lay out plan में कोई भी परिवर्तन नही किया जावेगा। आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–20)**
(xxii)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–21)**
(xxiii)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agenc or the project life, whichever is less;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–22)**
(xxiv)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–23)**
(xxv)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–24)**
(xxvi)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Van (Sanrakshan EvamSamvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–25)**
(xxvii)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–26)**
(xxviii)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	सभी शर्तो का पालन प्रतिवेदन e-portal (https://parivesh.nic.in/), पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, उप कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
02 प्रति में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विविध/115–899/ 1386 नवा रायपुर, दिनांक 06/06/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर / सरगुजा /रायपुर वृत्त छत्तीसगढ़।

– क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 08.02.2024 की सहपठित भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाईड लाईन दिनांक 29.12.2023 के नियम 10 अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत **एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।** किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नार्म्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।

2. **वन मंडलाधिकारी (नोडल)**, धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी**, कोरबा / जशपुर/बलौदा बाजार वन मंडल, छत्तीसगढ़
4. **परियोजना निदेशक**, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोरबा, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध/वन (सं एवं स)
छत्तीसगढ़